प्रजा फॉउण्डेशंन के अनुसार नब्बे प्रतिशत पार्षद का प्रदर्शन घटिया

मुंबई महानगपालिका के 24 वार्ड से 232 पार्षद चुन के आते है। इसके आलावा महानगपालिका के काम काज को सँभालने के लिए कुल 1.5 लाख कर्मचारी है। इन सबके आलावा महानगरपालिका का सालाना बजट 30 हजार करोड़ से 37 हजार करोड़ के बीच रहता है। वर्ष दो हजार सत्रह को पार्षद की सैलरी दस हजार से बढा के 25 हजार कर दी गयी। हलाकि समाजवादी पार्टी के रईस शेख चाहते थे की वेतन 50 हजार कर दिया जाये।

इन सबके के बावजूद अगर एक करोड़ पचास लाख से जयादा आबादी वाली इस शहर में अनियमिता रह जाये तो जनता की उपेक्षा पर सवाल तो उठेंगे ही। प्रजा फाउंडेशन ने पाया की सिर्फ 50 प्रतिशत पार्षदों ने सवाल पूछे वह भी 17 सवाल प्रति वर्ष। 99 प्रतिशत पार्षद नागरिको की शिकायत सुनाने को प्राथमिकता नहीं दी

प्रजा फॉउण्डेशंन की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम ने मालवणी के अम्बुजवाडी का दौरा किया। एक लाख प्रवासी मजदूर का यह इलाका बेहद ही अमानवीय स्थिति में है। हमने इसी तरह से धारावी का दौरा किया , बांद्रा झोपड़पट्टी भी गए और बोरीवली के दौलत नगर भी गए। सभी जगह स्थिति में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। कोरोना काल में जयादातर पार्षद नदारत ही रहे और तालाबंदी की मार झेल रहे मुम्बईकर अपने किये खुद ही समाधान ढूंढ रहे थे।

मनोज देसाई

एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मराठा मंदिर

आम जनता से भी अपील है की वह भी हमारे समर्थन में मुख्यमंत्री को लिखे की उन्हें थिएटर की जरूरत है। मेरे कई सारे कामगार राजीनामा देकर हमेशा के लिए चले गए है।उन्होंने अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर दिया है। वह वापस नहीं आने वाले है। जब भी थिएटर शुरू होगा तो हमे वापस नए भर्ती करनी पडेगी। आज सिनेमा जगत को वापस अपने पुराने स्वरुप में आने में कम से कम चार साल लग जायेंगे, वह भी तबजब बेहतरीन फिल्मे आएँगी। और सबसे बडी चुनौती OTT मीडियम है । बडी से बडी फिल्मे वह पर देखि जा रही है। हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा की हम वापस जनता को थिएटर में ला सके। एक बार अगर पब्लिक की आदत छूट जाती है थिएटर आने को लेकर तो वापस आदत दिलाने में वक्त लगता है। थिएटर ओनर एसोसिएशन ने सरकार से काफी बातचीत की है। पर हमारी तरफ कोई धयान नहीं दिया गया। बस इतना ही कहते है की अभी तो कोरोना चल रहा है। सोचते है।

Watch Asatya Bharat You Tube Channel for the complete interview